



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2019/श्रावण 30, 1941
No. 296]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2019/SHRAVANA 30, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 6 अगस्त, 2019

सं. टीएमपी/9/2019-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा तंगहाल पीपीपी परियोजनाओं पर पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्ष दिनांक 11 जुलाई, 2018 के अनुपालन में, डीवीओएफटी आधार पर वीपीटी के सामान्य नौभार गोदी में कोकिंग कोयला एवं वाष्प कोयले के मशीनीकृत प्रहस्तन हेतु विजाग जनरल कार्गो बर्थ प्राइवेट लिमिटेड (वीजीसीबीपलीएल) के नाम से दरमानों को अधिसूचित करते हुए इस प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी, 2013 द्वारा अनुमोदित भंडारण अनुसूची में संशोधन के लिए विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त इस प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/9/2019-वीपीटी

विशाखापट्टणम पत्तन न्यास

आवेदक

गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जुलाई 2019 के 24वें दिन पारित)

यह मामला डीबीओएफटी आधार पर वीपीटी के सामान्य नौभार गोदी में कोकिंग कोयला एवं वाष्प कोयले के मशीनीकृत प्रहस्तन हेतु विजाग जनरल कार्गो बर्थ प्राइवेट लिमिटेड (बीजीसीबीपीएल) के नाम से दरमानों को अधिसूचित करते हुए इस प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी, 2013 द्वारा अनुमोदित भंडारण अनुसूची में संशोधन के लिए विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. वीपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव में उल्लिखित बिंदु निम्नानुसार हैं:

- (i) टीएएमपी ने गोदी किराये पर लेने के लिए नौभार प्रहस्तन प्रभारों, भंडारण प्रभारों, और विविध प्रभारों के लिए दिनांक 27 नवंबर, 2009 के अपने आदेश में अग्रिम प्रशुल्क निर्धारित किया।
- (ii) वीपीटी ने वीपीटी में यह परियोजना बीजीसीबीपीएल को दी। यह परियोजना पूरी हो चुकी है और अप्रैल 2013 से परिचालन हो रहा है।
- (iii) बीजीसीबीपीएल ने अभिवेदन किया है कि उच्च भंडारण प्रभारों के परिणामस्वरूप व्यापार के समीपाव निजी पत्तनों को चले जाने से क्षमता के बहुत कम उपयोग जैसी अनेक दबावों के कारण से इस परियोजना का तंगहाली में परिचालन किया जा रहा है।
- (iv) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा आयोजित अनेक बैठकों में प्रमुख पत्तनों में पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित इस मुद्दे को उठाया गया। इस मुद्दे की महत्ता को ध्यान में रखते हुए पोत परिवहन मंत्रालय ने निर्णय लेने के लिए आईपीए के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। पोत परिवहन मंत्रालय ने समिति द्वारा प्रस्तुत इस रिपोर्ट को मिसिल संख्या डीपी-13/1/2018-पीपीपी सैल दिनांक 11-07-2018 द्वारा प्रमुख पत्तनों को अग्रेषित कर दिया है जिसमें टीएएमपी को निर्मित सुविधा के अधिकतम उपयोग हेतु स्थिति की आवधिक समीक्षा सहित इसमें उल्लिखित कार्य प्रणाली अपनाने का निदेश दिया है।

3. वीपीटी ने बीजीसीबीपीएल को टिप्पणियों के लिए मंत्रालय के निदेशों से अवगत करा दिया है। प्रत्युत्तर में, बीजीसीबीपीएल ने दिनांक 17.10.2018, 02.11.2018 और 12.11.2018 (अनुलग्नक-1, 2 एवं 3) के अपने पत्रों द्वारा समिति की रिपोर्ट के अनुसार “तंगहाल परियोजना” के वर्गीकरण के मानदंड के अनुसार संगत डाटा प्रस्तुत किया है। बीजीसीबीपीएल ने बीजीसीबीपीएल को तंगहाल परिसंपत्ति घोषित करने और मौजूदा निःशुल्क अवधि को 35 दिन अतिरिक्त बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। इससे कुल निःशुल्क अवधि 45 दिन हो जाएगी।

4. बीजीसीबीपीएल ने वीपीटी को संबोधित दिनांक 17 अक्टूबर, 2018, 2 नवंबर, 2018, और 12 नवंबर, 2018 के अपने पत्र निम्न अनुरोध किए हैं:

क. बीजीसीबीपीएल ने वीपीटी को संबोधित दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 के अपने पत्र में जिसे वीपीटी ने अपने प्रस्ताव के साथ अग्रेषित किया उसमें निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया है:

- (i) वे परियोजनाओं जिनकी पहचान असामान्य भंडारण प्रभारों के कारण से तंगहाल परियोजनाओं के रूप में की गई है उनकी संबंध में सुझाव दिया कि पीपीपी टर्मिनलों पर उगाहे भंडारण प्रभारों को पास में निजी संगठनों द्वारा संचालित गैर प्रमुख पत्तनों के प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2008 के अनुसार विवेकपूर्ण बनाया जाए।
- (ii) कोयला टर्मिनल के अग्रिम प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित कुल राजस्व के विभाजन के मानदंड निम्न हैं:

प्रशुल्क समूह	निर्धारित कुल राजस्व का परिणाम
कोयला प्रहस्तन प्रभार	98
भंडारण प्रभार	1
विविध प्रभार	1

निराधारा भंडारण प्रभारों के प्रस्तावित मॉडल बनाने से पहले बाजार की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करना उचित होगा।

(iii) **बाजार की वर्तमान स्थिति**

- (क) आबद्ध बिजलीघरों, स्पंज आयरन उत्पादकों, सीमेंट विनिर्माताओं इत्यादि को देश में कोयले की अनुपलब्धता के कारण से इस क्षेत्र में कोयलो के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई है। बाजार की वर्तमान स्थिति माल भाड़े का लाभ उठाने के लिए कैप पोतों से आयात के अनुकूल है।
- (ख) रेकों की उपलब्धता जहाजों के खाली करने का प्रमुख कारक है और इससे निःशुल्क भंडारण अवधि टर्मिनल से प्रहस्तन की व्यवसायिक व्यावहारिकता के आकलन का प्रमुख व्यवसायिक कारक है। गंगावरम पत्तन व्यापारियों और अंतिम प्रयोक्ता को माल के भंडारण एवं बिक्री के 90-120 दिन तक निःशुल्क भंडारण की सुविधा प्रदान करता है जिससे माल की सुपुर्दगी आसान हो जाती है तथा उनकी कार्यशील पूंजी का प्रवाह सुगम हो जाता है। ऐसे प्रतिस्पर्धी वातावरण में वीजीसीबीपीएल 30 से 60 दिन (औसतन 45 दिन) की निःशुल्क भंडारण सुविधा देने के लिए बाध्य है।
- (ग) बाजार में कोयले की अत्यधिक मांग के बावजूद, ग्राहक रेकों की अनुपलब्धता के जोखिम से बचने के लिए अधिक समय तक भंडारण कर रहे हैं। तथापि, हमारी टर्मिनल सुविधा के अधिकतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए, वीजीसीबीपीएल ने जहाजों की विविध क्षमता के लिए अपेक्षित व्यावहारिक भंडारण अवधि की गणना की है।

(iv) (क) **वर्तमान बाजार के आंकड़ें:**

विवरण	मूल्य	यूओएम
प्रतिदिन उपलब्ध रेकों की औसत संख्या	3.50	रैक
नौभार की प्रति रैक माल चढ़ाने की औसत मात्रा	3,850	एमटी
रैक से प्रति दिन औसत नौभार प्रेषण	13,475	एमटी
रैक से प्रतिमाह औसत नौभार प्रेषण	404250	एमटी
परिचालन दिवस	30	दिवस
विनियम दर (रुपए/अमेरिकी डॉलर)	72	रु./डॉलर

(ख) **जहाजों का प्रहस्तन संचय – पूर्वानुमान**

जहाज	जहाजों की संख्या	मात्रा	कुल यात्रा	औसतन माल उतराना	प्रति जहाज परिचालन दिवस	प्रति जहाज जीआरटी
केप	1	165,000	165,000	25,000	7	90,000
पनामा	3	75,000	225,000	25,000	3	40,000
कुल	4		390,000		16	

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि वीजीसीबीपीएल प्रांगण से औसत 30 दिन की निःशुल्क भंडारण अवधि से अधिक 400,000 एमटी का प्रहस्तन कर सकता है। यह अनिवार्य है कि अभी केवल वीजीसीबीपीएल अतिरिक्त 20 दिन की निःशुल्क भंडारण अवधि की लागत वहन करे। इस निःशुल्क भंडारण अवधि के अलावा भी टीएएमपी द्वारा निर्धारित प्रतिदिन के भंडारण प्रभारों और वीजीसीबीपीएल द्वारा वसूल की गई वास्तविक भंडारण दरों में भी अंतर है। वीजीसीबीपीएल पत्तन के ग्राहकों को रोके रखने के लिए अतिरिक्त निःशुल्क भंडारण अवधि उपलब्ध करा रहा है।

- (v) पोत परिवहन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप बीजीसीबीपीएल ने एक ऐसा व्यावसायिक मॉडल बनाया है जिससे मैसर्स बीजीसीबीपीएल और बीपीटी दोनों का लाभ होगा। यह निम्न है:

प्रस्तावित व्यावसायिक मॉडल

- (क) पत्तन के अधिकारियों को आवधिक समीक्षा की शर्त के साथ गोदी की क्षमता के अधिकतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर निशुल्क अवधि बढ़ाने का अवसर दिया गया। बीजीसीबीपीएल का मौजूदा निःशुल्क भंडारण के 10 दिन के अतिरिक्त 35 दिन (विस्तारित निःशुल्क दिन) तक निःशुल्क अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है। (अर्थात् कुल 45 दिनों की निशुल्क अंडारण अवधि)
- (ख) जहाजों के विस्तारित निशुल्क दिनों (अर्थात् 45 दिन) से अधिक रुकने पर प्रतिदिन 1 रु. प्रति एमटी का अधिकतम प्रशुल्क वसूल किया जायेगा। इस मॉडल के अन्य प्रमुख पूर्वानुमान निम्न हैं:

विवरण	मूल्य	यूओएम
प्रतिदिन उपलब्ध रैकों की औसत संख्या (पूर्वानुमान)	4.50	रैक
नौभार की प्रति रैक माल चढ़ाने की औसत मात्रा	3,850	एमटी
रैक से प्रति दिन औसत नौभार प्रेषण	17,325	एमटी
रैक से प्रतिमाह औसत नौभार प्रेषण	519750	एमटी
परिचालन दिवस	30	दिवस
विनियम दर (रुपए/अमेरिकी डॉलर)	72	रु./डॉलर

(vi) **अंतिम निष्कर्ष एवं प्रस्ताव**

बीजीसीबीपीएल ने उपरोक्त व्यावसायिक मॉडल के आधार पर निम्नलिखित प्रस्ताव किए हैं :

- (क) मौजूदा 10 निशुल्क भंडारण दिनों के अतिरिक्त निशुल्क अवधि को 35 दिन तक बढ़ाना (अर्थात् कुल 45 दिनों की निशुल्क भंडारण अवधि)।
- (ख) 45 दिन की निशुल्क भंडारण अवधि से अधिक अवधि तक रखने वाले जहाजों से 1 रु. पीएमटी प्रतिदिन (बीपीटी प्लॉट में वर्तमान में 0.10 रुपए पीएमटी प्रतिदिन और गंगावरम पत्तन में 90 से 120 दिन के लिए शून्य) के समान अथवा ऐसा प्रशुल्क जो इससे कम है, वसूल किया जाएगा।

[मुख्य परिचालन क्षेत्र में स्टैकिंग के लिए बीपीटी की मौजूदा दर सूची में 6.21/वर्ग मीटर/सप्ताह का उल्लेख है। बीपीटी की दरसूची में बीपीटी के प्लॉट में 0.10 रु.पा पीएमटी प्रतिदिन निर्धारित नहीं है।]

- (ग) ठहराव अवधि के निर्धारण के निहित पूर्वानुमान में बाजार की स्थितियों और संभार तंत्र की उपलब्धता के स्वतः परिवर्तन होगा एवं सुविधाओं के अधिकतम उपयोग इसकी आवधिक (प्रत्येक 6 माह में अथवा इसी तरह) समीक्षा की जा सकती है।
- (घ) बीजीसीबीपीएल ने पत्तन से महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण पोत परिवहन मंत्रालय हेतु परामर्श से तत्काल आधार पर विशाखापट्टणम पत्तन के प्रस्ताव को निवारक कार्रवाई के रूप में अधिसूचित करने का अनुरोध किया है ताकि टर्मिनल परिचालकों को तत्काल राहत दी जा सके।

ख. बीजीसीबीपीएल द्वारा बीपीटी को संबोधित दिनांक 2 नवंबर 2018 के पत्र में 45 दिन की प्रस्तावित निशुल्क अवधि के पीछे आधार:

- (i) कैप नौभार: किसी भी कैप जहाज में औसतन 1,65,000 एमटी की क्षमता होती है। अभी रैक उपलब्धता की स्थिति में इस श्रेणी के जहाज/ग्राहक को माल की निकासी के लिए प्रतिदिन एक रैक से अधिक आबंटित नहीं की जाती है। पूरे कैप जहाज से माल निकासी के लिए बीजीसीबीपीएल को कुल 42 रैकों (@ 3900 एमटी प्रति रैक की दर से) की आवश्यकता होगी। तदनुसार इस कार्य में 42 दिन लगेगे।

- (ii) पैनामैक्स जहाज: पैनामैक्स जहाजों में औसतन 75,000 एमटी माल होता है। अभी रैक उपलब्धता की स्थिति में ऐसे जहाज/ग्राहक माल निकासी के लिए प्रत्येक दो दिन में एक रैक से अधिक आबंटित नहीं की जाती है। पूरे पैनामैक्स जहाज से माल निकासी के लिए वीजीसीबीपीएल को कुल 19 रैकों (@ 3900 एमटी प्रति रैक की दर से) की आवश्यकता होगी। तदनुसार इस कार्य में 38 दिन लगेंगे।
- (iii) उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वीजीसीबीपीएल को पूरे जहाज (कैप जहाज अथवा पैनामैक्स जहाज) को वर्तमान में रैक की उपलब्धता के अनुसार माल निकासी में 40-45 दिन लगेंगे। यह उल्लेखनिय है कि उपरोक्त पुर्वानुमान से पूरे रैक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में माल निकासी के औसत समय में वृद्धि हो सकती है।

ग. वीजीसीबीपीएल ने दिनांक 12 नवंबर, 2018 के अपने पत्र द्वारा वर्ष 2016-17 और 2017-18 का वीजीसीबीपीएल का सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण अग्रेषित किया है। इस संबंध में नकदी/निवल परिसंपत्ति में कमी नीचे दी गई है:

- (i) वीजीसीबीपीएल द्वारा पूर्व में उपगत नकदी की कमी से वित्त वर्ष 2012-13 की 151.53 करोड़ रुपए की निवल परिसंपत्ति वर्ष 2017-18 में घट कर 21.70 करोड़ रुपए हो गई है।
- (ii) वीजीसीबीपीएल की सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित नकदी और निवल परिसंपत्ति में कमी निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	वि.वर्ष 2016-17 (करोड़ रुपए में)	वि.वर्ष 2017-18 (करोड़ रुपए में)
1	कंपनी द्वारा उपगत नकदी की कमी	(7.16)	(26.97)
2	कंपनी की निवल परिसंपत्ति	76.00	21.70

5.1. वीपीटी ने दिनांक 16 नवंबर 2018 को आयोजित वीपीटी की न्यासी मंडल की बैठक में वीजीसीबीपीएल का प्रस्ताव रखा। मंडल ने निम्न निश्चय किए हैं:

- (i) मैसर्स वीजीसीबीपीएल के उक्त परियोजना के “तंगहाल परियोजना” में वर्गीकरण के प्रस्ताव पर विचार करना और दिनांक 11 जुलाई 2018 को मंत्रालय के निदेशों के अनुपालन में परियोजना को तंगहाल परियोजना पालना।
- (ii) रियायत प्राप्तकर्ता मैसर्स वीजीसीबीपीएल के परामर्श से भंडारण प्रभारों को विवेकपूर्ण बनाने के उचित प्रस्ताव में “संशोधन, आशोधन अथवा एकांतरण” शामिल करते हुए रियायत करार के अनुच्छेद 21.9 में उपलब्ध प्रावधान के अंतर्गत टीएएमपी को प्रस्ताव करना ताकि टीएएमपी के दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं के अनुसार एआरआर निश्चित कि जा सके।
- (iii) टीएएमपी के प्रस्ताव में भंडारण प्रभारों को विवेकपूर्ण बनाने के लिए रियायत प्राप्तकर्ता और रियायत दाना दोनों द्वारा परस्पर सहमति के अनुसार रियायत करार में निर्धारित मौजूदा 10 दिन के निशुल्क भंडारण समय को 20 दिन करना रियायत प्राप्तकर्ता वीपीटी के माध्यम से टीएएमपी को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सूचित करना जिसमें भंडारण प्रभारों को विवेकपूर्व बनाने के लिए भंडारण अवधि में वृद्धि के कारण को न्यायोचित बताया गया हो।
- (iv) दिनांक 11.07.2018 के मंत्रालय के आदेशानुसार “संशोधनों, आशोधनों अथवा एकांतरणों” को शामिल करते हुए रियायत करार के अनुच्छेद 21.9 के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार आवश्यकत संशोधन करना।
- (v) एक वर्ष की अवधि और उसके पश्चात् समीक्षा के प्रस्ताव पर विचार करना।

5.2. वीपीटी ने वीपीटी मंडल के निर्णय से वीजीसीबीपीएल को अवगत कराया। वीजीसीबीपीएल ने वीपीटी को संबोधित दिनांक 13 दिसंबर 2018 के पत्र द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिसका सारांश निम्न है:

- (i) वीजीसीबीपीएल की अधिसूचना संख्या टीएएमपी/52/2007-मिस. दिनांक 26 फरवरी 2008 द्वारा अधिसूचित प्रमुख पत्तनों में सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) की परियोजनाओं का अग्रिम प्रशुल्क निर्धारित करने के दिशानिर्देशों

के अनुपालन में विशाखापट्टणम पत्तन में डीबीएफओटी आधार पर सामान्य नौभार गोदी में कोकिंग और वाष्प कोयले के मशीनी प्रहस्तन से संबंधित राजपत्र संख्या 250 द्वारा दिनांक 18 दिसंबर, 2009 को अधिसूचित इस प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएएम/58/2008-वीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009 द्वारा अनुमोदित दर सूची की अधिसूचना में संशोधन का प्रस्ताव करता है।

- (ii) वर्तमान दरसूची में निशुल्क भंडारण अवधि 10 दिन की है। इस अवधि पर इस परियोजना के प्रारंभ होने के समय विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर बोली के समय विचार किया गया है जबकि यह ध्यान में आया है कि ठहराव का औसत समय लगभग 20 से 25 दिन है। समग्र प्रहस्तन प्रभारों का प्रतिशत परिकलित भंडारण प्रभार टीएएमपी की दिनांक 26 फरवरी 2008 द्वारा अधिसूचित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के नीतिगत दिशानिर्देशों में विचार किए गए 1% से बहुत अधिक है।
- (iii) वीजीसीबीपीएल प्रशुल्क की वसूली से प्रस्तावित एआरआर प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए टीएएमपी प्रत्येक अलग-अलग सेवा के लिए प्रशुल्क की सीमा इस प्रकार निर्धारित करे कि अग्रिम प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 3.8.2. के अनुसार एआरआर प्राप्त किया जा सके।
- (iv) तंगहाल परिसंपत्तियों के लिए पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 11 जून 2018 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि वीपीटी को गोदी की क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए आवधिक समीक्षा के साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निःशुल्क अवधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक अधिकारी दे दिया गया है।
- (v) वर्तमान परिस्थितियों में, वीजीसीबीपीएल को तंगहाल परियोजना घोषित किया जाए और वीजीसीबीपीएल ने दिनांक 12 दिसंबर, 2018 के अपने पत्र में इसकी पुष्टि की है।
- (vi) चर्चाओं के कई दौर के पश्चात् निशुल्क भंडारण के मौजूदा 10 दिन (रियायत करार के अनुसार) को बढ़ाकर 20 दिन करने का निर्णय लिया गया है और वीपीटी भी इस निर्णय से सहमत है। प्रस्तावित निशुल्क अवधि बढ़ाने के लिए निम्न औचित्य दिए गए हैं:
 - (क) हस्ताक्षरित रियायती करार के अनुसार, प्रस्ताव की गई निशुल्क भंडारण अवधि 10 दिन है। यह टीएएमपी द्वारा दिनांक 27 नवंबर, 2009 के आदेश द्वारा निर्धारित अग्रिम प्रशुल्क का भाग है। इसका निर्णय उस समय की मौजूदा परिवर्तन-शील बाजार की परिस्थितियों के आधार पर बोली के समय किया गया था। जबकि वास्तव में यह पाया गया है कि बाजार की वर्तमान स्थिति वर्ष 2009 में विचार की गई स्थिति से बिल्कुल अलग है।
 - (ख) वीजीसीबीपीएल ने रैंक की उपलब्धता सहित बाजार की वर्तमान स्थितियों का उल्लेख करते हुए दिनांक 2 नवंबर 218 को वीपीटी को एक लिखा जिसमें उसने संशोधित निशुल्क भंडारण अवधि 45 दिन करने की मांग की है। बाद में वीपीटी के उपाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में जहाजों की वर्तमान ठहराव अवधि की जांच पड़ताल करने की सलाह दी गई। वीजीसीबीपीएल ने वीपीटी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 माह (वीपीटी द्वारा दिनांक 15 नवंबर 2018 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तुत आंकड़े) में प्रहस्तन किए गए जहाजों की ठहराव अवधि की गणना की और पाया कि औसतन ठहराव अवधि 20 से 25 दिन है। पिछली प्रचलित ठहराव अवधि के आधार पर रियायत प्राप्त कर्ता और रियायत दोनों निशुल्क अवधि 20 दिन तक बढ़ाने के लिए परस्पर सहमत हुए।
- (vii) वीपीटी ने पुष्टि करते हुए वीजीसीबीपीएल को सूचित किया कि वीपीटी ने पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 11 जुलाई 2018 के पत्र के द्वारा निकाला जाता है तो रियायत प्राप्तकर्ता वास्तव में वसूल किए गए भंडारण प्रभारों के लिए उद्धृत प्रतिशत के समान रॉयल्टी अथवा एआरआर के 1% इनमें जो भी अधिक हो उसका भुगतान करेगा:
 - (क) निष्पादन रियायत करार के अनुसार यदि जहाज को निशुल्क अवधि (अर्थात् 10 दिन में) निकाल दिया जाता है तो कोई भंडारण प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा इसलिए कोई रॉयल्टी नहीं जाएगी।
 - (ख) यदि जहाज निष्पादन रियायत करार के अनुसार निशुल्क समापन अवधि के पश्चात् परंतु विस्तारित निशुल्क अवधि में निकाला जाता है तो कोई भंडारण प्रभार वसूली नहीं किया जाएगा परंतु रियायत प्राप्तकर्ता एआरआर के 1% के बराबर रॉयल्टी का भुगतान करेगा और

- (ग) यदि जहाज विस्तारित निशुल्क अवधि (अर्थात् 20 दिन से अधिक) के पश्चात् निकाला जाता है तो रियायत प्राप्तकर्ता वास्तव में वसूल किए गए भंडारण प्रभारों के लिए प्रदत्त प्रतिशत के समान रॉयल्टी अथवा एआरआर के 1% इनमें जो भी अधिक हो उसका भुगतान करेगा।

(viii) तदनुसार, वर्तमान और प्रस्तावित दर सूची निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	वर्तमान दर सूची	प्रस्तावित दर सूची
1.	गोदी किराया प्रभार	रु./जीआरटीएच	0.851	0.851
2.	कार्गो प्रहस्तन प्रभार	रु./ एमटी	171.69	171.69
3.	भंडारण प्रभार (0-10 दिन)	रु./एमटी प्रति दिन	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
4.	भंडारण प्रभार (11-15 दिन)	रु./एमटी प्रति दिन	2.06	कोई परिवर्तन नहीं
5.	भंडारण प्रभार (16-20 दिन)	रु./एमटी प्रति दिन	4.11	कोई परिवर्तन नहीं
6.	भंडारण प्रभार 46 ^{वें} दिन से आगे	रु./एमटी प्रति दिन	8.22	8.22
7.	विविध प्रभार (झाड़ू लगाने, धूल दमन और पर्यावरण आदि के प्रभार)	रु./ एमटी	1.76	1.76

[यह संशोधन केवल भंडारा प्रभारों में प्रस्तावित है।]

(ix) इसके अतिरिक्त, भंडारण प्रभारों पर वर्तमान और प्रस्तावित रॉयल्टी निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	*मौजूदा रायल्टी	*प्रस्तावित रायल्टी
1.	भंडारण प्रभार (0-10 दिन)	रु./एमटी प्रति दिन	कोई रायल्टी नहीं	कोई रायल्टी नहीं
2.	भंडारण प्रभार (11-15 दिन)	रु./एमटी प्रति दिन	सकल राजस्व पर 38.1%	1% एआरआर
3.	भंडारण प्रभार (16-20 दिन)	रु./एमटी प्रति दिन	सकल राजस्व पर 38.1%	1% एआरआर
4.	भंडारण प्रभार 21 ^{वें} दिन से आगे	रु./एमटी प्रति दिन	सकल राजस्व पर 38.1%	वसूल किये गए वास्तविक भंडारण प्रभार के 38.1% के समान रायल्टी अथवा एआरआर का 1% जो भी अधिक हो।

[* इस प्राधिकरण का अधिकार दरमान निर्धारित करना है। टीएएमपी को पत्तन और संबंधित वीओटी परिचालकों के मध्य रॉयल्टी मामले में अधिकार नहीं है।]

(x) तदनुसार, वीजीसीबीपीएल ने वीपीटी से प्राधिकरण के परामर्श ऐसे आदेश प्राप्त करने का अनुरोध किया है जो वर्ष 2008 अग्रिम प्रशुल्क दिशानिर्देशों के पैरा 1.4 के अनुसार कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक वर्ष 2008 के दिशानिर्देशों से असंगत नहीं हो।

5.3. वीपीटी ने इस प्राधिकरण से वीजीसीबीपीएल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने और जहाजों को समीपस्थ निजी पत्तन पर जाने से रोकने एवं व्यापार बढ़ाने के लिए प्रस्ताव को शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचित करने का अनुरोध किया है ताकि इस सुविधा के क्षमता उपयोग को अनुमोदित किया जा सके। आगे, वीपीटी ने बताया है कि वह वीपीटी मंडल के संकल्प के अनुपालन में इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना के एक वर्ष के पश्चात् प्रस्तावित पुनःनिर्धारण की समीक्षा करेगा और इस प्राधिकरण से प्रस्ताव जारी रखने अथवा आगे संशोधन के लिए, जैसा भी मामला हो, संपर्क करेगा।

6. वीपीटी ने निर्धारित परामर्शक प्रक्रिया के अनुसार संलग्नकों के साथ दिनांक 7 दिसंबर 2018 के प्रस्ताव को संबंधित उपयोग कर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया है हमें केवल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं जिसे फीडबैक के लिए वीपीटी को अग्रेषित कर दिया गया है। वीपीटी ने इस मामले पर निर्णय करने तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

7. संदर्भाधीन इस मामले पर वीपीटी परिसर में दिनांक 17 जून 2019 को एक संयुक्त सुनवाई हुई। संयुक्त सुनवाई में वीपीटी और वीजीसीबीपीएल ने अपनी प्रस्तुतियों दी।

8. वीजीसीबीपीएल के लाभ पर एसजीआर को अधिसूचित करते हुए अग्रिम प्रशुल्क आदेश 27 नवंबर 2009 और प्रशुल्क आदेश 11 जनवरी 2013 में निर्धारित भंडारण प्रभार सूची और प्रासंगिक नाते का संबद्ध सार नीचे दिया गया है:

(i) आदेश संख्या टीएएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009:

“4. भंडारण प्रभार:

खाली समय के अलावा स्टैक यार्ड में स्टोर किए गए कार्गो के लिए भंडारण प्रभार निम्न प्रकार होगा:

(दर रु. प्रति टन प्रति दिन या उसके अंश में)

क्र.सं.	वस्तु	निशुल्क अवधि के बाद शेष के कार्गो के लिए पहले पांच दिन हेतु दर	शेष कार्गो के लिए 6वें दिन से 10 वें दिन तक हेतु दर	शेष कार्गो के लिए 11 दिन तथा आगे के लिए दर
1.	कोकिंग कोयला और स्टीम कोक	1.58	3.16	6.32

टिप्पणी:

10 निशुल्क दिन प्रदान किये जाएंगे। पोत से कार्गो पूरी तरह उतार लिए जाने वाले दिन के अगले दिन से निशुल्क अवधि की गणना के लिए सीमा शुल्क अधिसूचित छुट्टी और टर्मिनल के गैर कामकाजी दिन शामिल नहीं किए जाएंगे।”

(ii) आदेश संख्या टीएएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी 2013:

“4. भंडारण प्रभार:

खाली समय के अलावा स्टैक यार्ड में स्टोर किए गए कार्गो के लिए भंडारण प्रभार निम्न प्रकार होगा

(दर रु. प्रति टन प्रति दिन या उसके अंश में)

क्र.सं.	वस्तु	निशुल्क अवधि के बाद शेष के कार्गो के लिए पहले पांच दिन हेतु दर	शेष कार्गो के लिए 6वें दिन से 10 वें दिन तक हेतु दर	शेष कार्गो के लिए 11 दिन तथा आगे के लिए दर
1.	कोकिंग कोयला और स्टीम कोक	1.80	3.59	7.19

टिप्पणी:

10 निशुल्क दिन प्रदान किये जाएंगे। पोत से कार्गो पूरी तरह उतार लिए जाने वाले दिन के अगले दिन से निशुल्क अवधि की गणना के लिए सीमा शुल्क अधिसूचित छुट्टी और टर्मिनल के गैर कामकाजी दिन शामिल नहीं किए जाएंगे।”

9.1. पोत परिवहन मंत्रालय ने तंगहाल सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के संबंध में दिनांक 11 जुलाई 2018 के अपने ई-मेल द्वारा पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी दिनांक 11 जुलाई 2018 किया जिसके साथ तंगहाल पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित मामलों पर अध्यक्ष आईपीए की अध्यक्षता वाली समिति की प्रति भी संलग्न थी। उक्त समिति ने “तंगहाल परियोजनाओं” के रूप में वीपीटी परियोजना के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित मानदंड की सिफारिश की है:

- (क) परियोजना का उपयोग कम हुआ है जैसा पिछले वित्त वर्षों के दौरान प्रचालक द्वारा वास्तव में बोली दस्तावेजों के एक भाग के रूप में डीपीआर/व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार प्रक्षेपण के 70% से भी कम कार्गो प्रहस्तन हुआ है।
- (ख) परियोजना एसपीवी पिछले दो वित्त वर्षों में लगातार नकद हानि वहन कर रहा है।
- (ग) कि ग्राही द्वारा वहन हानियों से प्रचालन अवधि के दौरान उसकी उच्च नेट-वर्थ में कम से कम 50% का क्षरण हुआ है।

9.2. पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 11 जुलाई 2018 के पत्र का पैरा 6 बताता है कि जब भी असामान्य भंडारण प्रभार का मामला तंगहाल परियोजना में शामिल होता है, जैसा पोत परिवहन मंत्रालय पत्र में यथा परिभाषित है तो पोर्ट छूट ग्राही के साथ परामर्श से भंडारण प्रभार के युक्तिकरण के लिए उपयुक्त प्रस्तावों सहित रियायत अनुबंध का निबंधन एवं शर्तों की "अनुबंध, संशोधन अथवा परिवर्तन" के प्रावधानों के अंतर्गत टीएएमपी को अप्रोच कर सकते हैं ताकि टीएएमपी दिशानिर्देशों अधिसूचना के अनुसार एआरआर को प्राप्त कर सके। इस प्राधिकरण को ऐसे प्रस्तावों का योग्यता के आधार पर विचार करना होगा। समिति ने सृजित सुविधाओं के अनुकूल उपयोग के लिए छूट देने वाले प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति की अवधिक समीक्षा की सिफारिश भी की।

9.3. पोत परिवहन मंत्रालय के उक्त पत्र के संदर्भ में वीपीटी ने वीपीटी स्थिति डीबीएफओटी में सामान्य कार्गो बर्थ पर कुर्किंग कोयला और स्टीम कोयला की संभलाई करने वाली प्रणाली के लिए इस प्राधिकरण द्वारा आर्डर दिनांक 27 नवंबर 2009 के मानदंड सं. अनुमोदित अग्रिम प्रशुल्क पर आधारित वीजीसीबीपीएल के नाम में अनुक्रानित प्रशुल्क की अधिसूचना करते हुए आदेश संख्या टीएएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी 2013 में इस प्राधिकरण में अनुमोदित भंडारण सूची के संशोधन के लिए वर्तमान प्रस्ताव को संलग्न किया गया।

10.1. वीपीटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अनुमोदन के आधार पर निःशुल्क अवधि में विस्तार और भंडारण सूची में संशोधन के लिए वीपीटी का प्रस्ताव केवल निर्धारित परामर्श प्रक्रिया के बाद ही अधिसूचना के लिए तैयार हो पाएगा, जिसमें समय लगेगा। अतः कार्गो के भंडारण के लिए निःशुल्क अवधि में विस्तार के लिए वीपीटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा सस्वीकृत अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए, और वीपीटी द्वारा व्यक्त अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए वीजीसीबीपीएल के मौजूदा भंडारण सूची में संशोधन के लिए वीपीटी के प्रस्ताव की संद्धान्तिक अनुमोदन की स्वीकृति दी गई जैसा नीचे दिया गया है कि इस प्राधिकरण के लंबित अनुमोदन और भारत के राजपत्र में इसकी सूचना निर्धारित परामर्श प्रक्रिया के बाद किया गया तथा अपनी पत्र दिनांक 21 जनवरी 2019 द्वारा वीपीटी को सूचित किया गया था:

भंडारण प्रभार:

(प्रतिदिन अथवा उसके भाग पर प्रति टन रु. में)

क्र.सं.	भंडारण दिन	वर्तमान एसओआर के अनुसार वीजीसीबीपीएल की मौजूदा दरें	संशोधित भंडारण प्रभार
1.	0-10 दिन	शून्य	शून्य
2.	11-15 दिन	2.06	कोई परिवर्तन नहीं
3.	16-20 दिन	4.11	कोई परिवर्तन नहीं
4.	21वें दिन से आगे	8.22	8.22

10.2. वीपीटी के उस प्रस्ताव के संबंध में जिसे वीजीसीबीपीएल द्वारा देय राजस्व हिस्से में भी शामिल किया गया है, वीपीटी के ध्यान में लाया गया कि वीजीसीबीपीएल द्वारा वीपीटी को देय भंडारण प्रभार पर राजस्व हिस्से को प्रतिशतता को तंगहाल पीपीपी परियोजनाओं पर जारी पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र सं. पीडी-13/1/2018-पीपीपी सेल के अनुसार शामिल निर्धारित किया जाएगा।

11. बाद में, वीपीटी ने पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र दिनांक 11 जुलाई 2018 में निर्धारित प्रथम मानदंड के संबंध में निम्नलिखित की स्पष्ट किया:

- (i) 'तंगहाल परियोजना' के रूप में पीपीपी परियोजना के वर्गीकरण के लिए मानदंड 3(क) में यह निर्धारित किया गया कि "निविदा दस्तावेज के भाग होने वाली डीपीआर/व्यवहारिता रिपोर्ट के अनुसार 70% अनुमान कम होने के कारण पूर्ववर्ती वित्त वर्षों के दौरान ऑपरेटर द्वारा संभाले गए वास्तविक कार्गो द्वारा यथा साक्ष्य के रूप में परियोजना का अपष्टतम रूप सं. उपयोग किया है।"
- (ii) इस संबंध में वीपीटी ने दिनांक 16.11.2018 को हुई आयोजित अपनी बैठक में तंगहाल परियोजना के रूप में वीजीसीबीपीएल को मानने हेतु मत रखा। उक्त मानदंड के संदर्भ में तंगला परियोजना के रूप में परियोजना के

वर्गीकरण के लिए वीपीटी बोर्ड द्वारा विचार किए गए बीजीसीबीपीएल के उपयोग का दर्शाने वाला विवरण निम्न प्रकार दिया गया है:

वर्ष	मात्रा (एमएमटी)	उपयोगिता %
2016-17	4.25	42%
2017-18	5.53	54%

12.1. आगे, बीजीसीबीपीएल का उसके दिनांक 10 जुलाई 2019 के पत्र द्वारा प्रस्तुतियों का संक्षेप में निम्न प्रकार है:

- (i) प्राधिकरण ने बीजीसीबीपीएल के नाम में दरमानों (एसओआर) को अधिसूचित करते हुए आदेश संख्या टीएएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11.01.2013 के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भंडारण सूची में संशोधन के लिए जब परामर्श को पूरा कर लिया है। जब परामर्श वीपीटी कार्यालयों में दिनांक 17.06.2019 को आयोजित किया गया।
- (ii) बीजीसीबीपीएल द्वारा इस परियोजना को इसके व्यवसायिक प्रचालन हेतु दिनांक 08.04.2013 को शुरू की गई थी और जहाज के आकार के आधार पर प्रतिदिन 42000 से 70000 मीट्रिक टन की उतराई क्षमता को निर्धारित किया गया था जो 10 दिन की निःशुल्क भंडारण अवधि, और दस रेलवे रैक प्रतिदिन की प्रत्याशित उपलब्धता के साथ थी।
- (iii) 2008 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) पर प्राधिकरण दिशानिर्देशों के अनुसार कोल प्रहस्तन टर्मिनल को संभलाई प्रभार के माध्यम से 98% राजस्व, भंडारण प्रभार के माध्यम से 1% राजस्व और विविध प्रभारों के प्रति 1% राजस्व अर्जित करना पड़ेगा। तथापि, चूंकि प्रचालन दिनांक 08.04.2013 से शुरू हुआ इसलिए सभी हितधारकों सहित पोत परिवहन मंत्रालय, वीपीटी और टीएएमपी जा नोट किया कि वीपीटी स्थित बीजीसीबीपीएल टर्मिनल ने भंडारण प्रभार से राजस्व लगभग 25 से 45 प्रतिशत (1% के अलावा) जो असामान्य है और इस टर्मिनल को समीपवर्ती छोटे पोर्ट की ओर ले जा रहा है।
- (iv) जुलाई 2018 में जब पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी सेल दिनांक 11.07.2018 द्वारा सिफारिश की है कि मुख्य पोर्ट छूट ग्राहियों के साथ परामर्श से भंडारण प्रभार के युक्तिसंगत प्रक्रिया को अपनाएं जिससे कि टीएएमपी दिशानिर्देश/अधिसूचना के अनुसार वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) को प्राप्त कर सके और टीएएमपी से कहा गया कि वह योग्यता के आधार पर प्रस्ताव पर विचार करें।
- (v) संशोधन करते समय बीजीसीबीपीएल ने छूट देने वाले दोनों प्राधिकरण से बात करके आवश्यक कार्य को करने का अनुरोध किया तथा छूट ग्राही दरमानों में परिवर्तन के प्रभाव की गणना के लिए परस्पर स्वीकार्य प्रभाव तिथि रखें।

12.2. उक्त सूचना में बीजीसीबीपीएल द्वारा बनाया गया बिंदु संख्या (v) है।

13. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्रवाई इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए मतों का सार उनको पृथक् रूप से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

14. मामले की प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आती है:

- (i) विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव तंगहाल पीपीपी परियोजनाओं से निपटने के संबंध में पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) द्वारा सभी महापत्तनों को जारी 11 जुलाई, 2018 के पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्ष के अनुपालन में वीपीटी में प्रचालन कर रहे बीओटी प्रचालक अदानी विजाग कोक टर्मिनल प्रा.लि. (एवीसीटीपीएल) के दरमान में मौजूदा निशुल्क अवधि में वृद्धि और मौजूदा भंडारण अनुसूची में संशोधन चाहता है; जो अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 द्वारा शासित है।
- (ii) जैसा पहले के पैराग्राफ में बताया जा चुका है कि इस प्राधिकरण ने पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी और 26 फरवरी 2008 से प्रभाव 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुपालन में 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अंतर्गत वीपीटी स्थित डिजाइन बिल फाइनेंश ऑपरेटर एंड ट्रांसफर (डीबीएफओटी) आधार पर अपने जनरल कार्गो

वर्थ (सीजीबी) में कुकिंग कोल और स्टीम कोल की संभलाई प्रणाली के लिए अप्रेंट प्रशुल्क के निर्धारण के संबंध में आदेश संख्या टीएएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009 द्वारा एक आदेश पारित किया था।

वीपीटी ने मैसर्स वीजीसीबीपीएल को परियोजना कार्य दिया। दिशानिर्देशों के उक्त प्रावधानों के अनुपालन में इस प्राधिकरण द्वारा 27 नवंबर 2009 को अनुमोदित आदेश सं. अधिसूचित अप्रेंट प्रशुल्क का सूचीकरण करने के बाद आदेश संख्या टीएएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी 2013 द्वारा वीजीसीबीपीएल के नाम में दरमानों अधिसूचित किए थे।

- (iii) वीपीटी के वर्तमान प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि इसे तंगहाल पीपीपी परियोजना के संबंध में प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का दिनांक 11 जुलाई 2018 के अनुपालन में प्रस्तुत किया गया है।
- (iv) पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 11 जुलाई 2018 में प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट द्वारा तंगहाल परियोजना के रूप में पीपीपी परियोजना के वर्गीकरण के लिए तीन मानदंड निर्धारित किए जो पैरा 9.1 में सामने लाए गए और इसी कारण से संक्षिप्तता के लिहाज से दोहराया नहीं गया। वीपीटी के न्यासी मंडल ने वीजीसीबीपीएल द्वारा रख-रखाव की गई परियोजना को तंगहाल परियोजना के रूप में घोषित किया। पोर्ट ने पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र में निर्दिष्ट तीन मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जिन पर वीजीसीबीपीएल की परियोजना की तंगहाल परियोजना के रूप में घोषित करने के लिए वीपीटी के न्यासी मंडल द्वारा विचार किया गया:

- (क) जहां तक पहले प्रतिमान का संबंध है, पिछले 2 वर्षों का क्षमता उपयोग, वीपीटी द्वारा यथा प्रस्तुत, 70% से भी कम रहा है, जैसा वीपीटी ने प्रदर्शित किया है, नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:-

वर्ष	संभाले गए कार्गो की मात्रा (एमएमटी)	उपयोग %
2016-17	4.25	42%
2017-18	5.53	54%

- (ख) अन्य दो प्रतिमानों के संबंध में पोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण प्रस्तुत किया जिसमें दो पूर्ववर्ती वित्त वर्षों के लिए निरंतर नकद हानि और पूर्ववर्ती दो वर्षों में 50% से पार शुरू कीमत में की सूचना दी गई:

क्र.सं.	विवरण	वि.वर्ष 2016-17 (करोड़ रु. में)	वि.वर्ष 2017-18 (करोड़ रु. में)
1	कंपनी द्वारा वहन की गई नकद हानि	(7.16)	(26.97)
2	कंपनी की निवल संपत्ति	76.00	21.70

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2016-17 में 7.16 करोड़ रुपए की नकद हानि वित्त वर्ष 2017-18 में 26.97 करोड़ रु तक बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त वीजीसीबीपीएल की निवल संपत्ति वित्त वर्ष 2016-17 में 76 करोड़ रुपए से घटकर वित्त वर्ष 2017-18 में 21.70 करोड़ रुपए हो गई जो 71% अर्थात् तंगहाल परियोजना के रूप में परियोजना को बताने वाले किसी एक मापदंड के रूप में निर्दिष्ट न्यूनतम 50% कमी से अधिक है।

- (v) 27 नवंबर, 2009 के आदेश द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान और इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान और वीजीसीबीपीएल के नाम से अधिसूचित, में अनुसूची 4 के नीचे टिप्पणी संख्या 1 के रूप में निशुल्क अवधि के लिए निम्नलिखित उपबंध निर्धारित है।

“10 निशुल्क दिन प्रदान किये जाएंगे। पोत से कागों पूरी तरह उतार लिए जाने वाले दिन के अगले दिन से निशुल्क अवधि की गणना के लिए सीमा शुल्क अधिसूचित छुट्टि और टर्मिनल के गैर कामकाजी दिन शामिल नहीं किए जाएंगे।”

पत्तन का निशुल्क अवधि को मौजूदा 10 दिन से बढ़ाकर 20 दिन करने और परिणामस्वरूप मौजूदा अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, इस प्राधिकरण के 27 नवंबर, 2009 के आदेश में अनुमोदित अप्रेंट प्रशुल्क में भंडारण अनुसूची और 11 जनवरी, 2013 के वीजीसीबीपीएल के नाम से अधिसूचित दरमान के अनुसार, वर्ष 2018-19 और अप्रैल, 2019 से चालू वर्ष 2019-20 के लिए स्वतः सूचकांकन लागू करने के पश्चात् मौजूदा लागू दर तथा वीपीटी द्वारा प्रस्तावित दर तथा दर में मामूली से संशोधन के पश्चात् इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भंडार प्रभारों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी जा रही है:

(रु./एमटी टन प्रति दिन और प्रति दिन)

क्र.सं.	विवरण	प्रभार प्राधिकरण के 27 नवंबर 2009 के आदेश में अनुमोदित भंडारण	सूचकांकन कारक लागू करने के पश्चात् 11 जनवरी, 2013 के वीजीसीबीपीएल के नाम से अधिसूचित दरमान के अनुसार अधिसूचित दरमानों में भंडारण प्रभार	सूचकांकन कारक लागू करने के पश्चात् 2018-19 के लिए लागू भंडारण प्रभार	7 दिसंबर 2018 के पत्र में वीपीटी द्वारा प्रस्तावित भंडारण प्रभार	मौजूदा अनुमोदित दर पर 1 अप्रैल 2019 से लागू वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक सूचकांकन कारक लागू करके अद्यतन करने के पश्चात् वीपीटी द्वारा प्रस्तावित भंडारण प्रभार
1.	भंडारण प्रभार (0-10 दिन)	शून्य	शून्य	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
2.	भंडारण प्रभार (11-15 दिन)	1.58	1.80	2.06	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
3.	भंडारण प्रभार (16-20 दिन)	3.16	3.59	4.11	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
4.	भंडारण प्रभार 21वें दिन से आगे	6.32	7.19	8.22	8.22 *	8.22 * (21.01.2019 से 31.03.2019 तक) ## 8.43 # (01.04.2019 से 20.01.2020 अब तक)

(* वर्ष 2018-19 के लिए लागू भंडारण प्रभार को वर्ष 2017-18 तक आधार वर्ष 2019 के पार 27.49% के लागू संयोजित सूचीकरण और वर्ष 2018-19 के लिए 2.07% के वार्षिक सूचीबद्ध को लागू करने के बाद प्राप्त किया गया।)

वर्ष 2019-20 के लिए लागू भंडारण प्रभार इस प्राधिकरण के वर्ष 2019-20 के लिए 29 मार्च, 2019 के पत्र संख्या टीएएमपी/12/2009-विविध के द्वारा घोषित 2.56% के वार्षिक सूचकांकन लागू करने के पश्चात् निकाला गया है।

21.01.2019 सिद्धांत रूप से अनुमोदन के संसूचन की तारीख है।)

(vi) यह मानते हुए कि वीपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव वीपीटी के न्यासी मंडल के अनुमोदन पर आधारित है और तंगहाल परियोजना पर पोत परिवहन मंत्रालय पत्र दिनांक 11 जुलाई 2018 पर आधारित है तथा एक वर्ष की अवधि के लिए है और इसके बाद वीपीटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा समीक्षा की जाएगी एवं दोनों पक्षकारों अर्थात् वीपीटी और वीजीसीबीपीएल द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकृत है, तथा सृजित सहवधा कि उपयोग में सुधार करने के इच्छुक हैं इसलिए यह प्राधिकरण पोर्ट के वर्तमान प्रस्ताव का अनुमोदन करने को तैयार है। वीपीटी ने दिसंबर 2018 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चूंकि इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अप्रेंट प्रभार में स्वतः वार्षिक सूचीकरण पत्र संख्या टीएएमपी/12/2009-मिस. दिनांक 29 मार्च, 2019 के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से वर्ष 2019-20 के लिए लागू है

इसलिए 1 अप्रैल 2019 से 2.56% स्वीकार्य वार्षिक सूचीकरण फैक्टर को लागू करने के बाद, जैसा प्राधिकरण ने बताया है, अद्यतन भौडार प्रभार अर्थात् वीपीटी द्वारा प्रस्तावित 8.22 रु./प्रति टन/ प्रति दिन अथवा इसके भाग परी के सथान पर 8.43 रु./टन/ प्रति दिन अथवा उसके भाग पर को शामिल करने की आवश्यकता है।

- (vii) पूर्ववर्ती पैराग्राफ में जैसा दर्शाया गया है कि उल्लिखित कारणों के लिए हमारे पत्र दिनांक 21 जनवरी 2019 द्वारा 7 दिसंबर 2018 के वीपीटी प्रस्ताव को संद्धान्तिक अनुमोदन की स्वीकृति दी गई थी। जैसा पहले बताया गया कि वीपीटी के बोर्ड ने एक वर्ष के लिए प्रस्ताव के अनुमोदन तथा उसके बाद समीक्षा की स्वीकृति दी है। ऐसा होने पर संशोधित भंडारण सूची की वैधता को इस प्राधिकरण द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए 21 जनवरी 2019 से 20 जनवरी 2020 तक अनुमोदित किया। संशोधित सूची को उस स्थिति में स्वतः ही समाप्त माना जाएगा तथा लागू सूचीकरण के साथ दिनांक 11 जनवरी 2013 द्वारा यथा अधिसूचित वास्तविक भंडारण सूची 21 जनवरी 2020 से लागू हो जाएगी जब तक कि वीपीटी द्वारा समीक्षा नहीं की जाती और इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता।
- (viii) वीजीसीबीपीएल द्वारा दिए गए बिंदु के संबंध में जिसमें वीपीटी और वीजीसीबीपीएल दोनों पक्षकारों से सुनवाई की पारस्परिक स्वीकार्य प्रभावी तिथि निर्धारित करने के लिए कहकर आवश्यक कार्य करने के लिए कहा गया था इस संबंध में यह बताया जाता है कि पोत परिवहन मंत्रालय ने तंगहाल पीपीपी परियोजनाओं के लिए सभी मुख्य पत्तनों को पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी सैल दिनांक 11 जुलाई 2018 जारी किया। पोत परिवहन मंत्रालय के उक्त पत्र में प्रमुख पोर्ट ट्रस्टों से यह अपेक्षित है कि वे पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट तंगहाल परियोजना के लिए मापदंड आधारित तंगहाल परियोजना के संबंध में छूट ग्राही के साथ परामर्श से भंडारण प्रभारों के युक्तिसंगत हेतु उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करें। वीपीटी ने पोत परिवहन मंत्रालय के उक्त पत्र के अनुपालन में और 16 नवंबर 2018 पर इसके बोर्ड द्वारा स्वीकृत अनुमोदन के साथ 7 दिसंबर 2018 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस आदेश के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित कारणों के लिए निःशुल्क अवधि में बढोत्तरी और युक्तिसंगत भंडारण प्रभार हेतु वीपीटी के प्रस्ताव की 21 जनवरी 2019 से एक वर्ष अर्थात् 20 जनवरी 2020 तक के लिए अनुमोदन हेतु सिफारिश की गई और यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा जब तक वीपीटी द्वारा समीक्षा नहीं ली जाते और इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता। वीजीसीबीपीएल और वीपीटी के मध्य पारस्परिक रूप से स्वीकार्य प्रभावी तिथि के लिए वीजीसीबीपीएल द्वारा तैयार किए गए बिंदु के संबंध में यह वीपीटी और वीजीसीबीपीएल के लिए है कि वे मामले को देखें।
- (ix) वीपीटी के प्रस्ताव में संदेय रायल्टी का भी प्रस्ताव भी किया गया है, जैसी पहले के पैरा में चर्चा की गई है। इस संबंध में, यह बताया जाता है कि इस प्राधिकरण को दरमान निर्धारित का अधिदेश प्राप्त है। इस प्राधिकरण को रायल्टी संबंधी मामलों पर अधिदेश प्राप्त नहीं है जो पत्तन और संबंधित बीओटी प्रचालक के बीच का मामला है। इस प्रकार, जहां तक वीजीसीबीपीएल द्वारा वीपीटी को संदेय भंडारण प्रभारों पर राजस्व हिस्से की प्रतिशत कबरेज पर वीपीटी के प्रस्ताव का संबंध है, यह बताया जाता है कि पत्तन पोत परिवहन मंत्रालय के 11 जुलाई, 2018 के पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्ष द्वारा शासित है। यह स्थिति हमारे 21 जनवरी, 2019 के पत्र में पहले ही स्पष्ट कर दी गई है।
- (x) चूंकि वीपीटी का वर्तमान प्रस्ताव एक वर्ष की अवधि तक के लिए समिति है और यह मान्य करते हुए कि वीजीसीबीपीएल के नाम से अधिसूचित भंडारण प्रभार और निशुल्क अवधि, वार्षिक वृद्धि के अधीन पूरी परियोजना के लिए है, यह निर्धारित करना उपयुक्त पाया जाता है कि मौजूदा टिप्पणी (i) निशुल्क अवधि में 10 दिन से 20 दिन की वृद्धि के बारे में और वीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधित भंडारण अनुसूची को अलग रखा जाए कि 11 जनवरी 2013 के आदेश संख्या टीएएमपी/58/2008-वीपीटी में इस प्राधिकरण द्वारा वीजीसीबीपीएल के नाम से अनुमोदित मौजूदा दरमानों से छेड़छाड़ की जाए। उक्त आदेश में अधिसूचित दरमानों में अनुसूची 4 के अनुसार भंडारण प्रभार से संबंधित टिप्पणी संख्या (ii) और (iii) को सुगमता के लिए निर्धारित किया जाता है।

15.1. परिणाम में, और ऊपर दिये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण 11 जनवरी 2013 के आदेश संख्या टीएमपी/58/2008-वीपीटी में इस प्राधिकरण द्वारा बीजीसीबीपीएल के नाम से अनुमोदित दरमानों में अनुसूची 4 के अनुसार भंडारण प्रभार से संबंधित मौजूदा अनुसूची को निम्नलिखित अनुसूची से प्रतिस्थापित किया जाता है:

(रु. में प्रति टन/प्रति दिन या उसका भाग)

क्र.सं.	विवरण	लागू सूचकांकन के पश्चात् वर्ष 2018-19 के लिए लागू भंडारण प्रभार	लागू सूचकांकन के पश्चात् वर्ष 2019-20 के लिए लागू मौजूदा भंडारण प्रभार	21.1.2019 से 31.3.2019 तक संशोधित भंडारण प्रभार	1.4.2019 से 20.1.2020 तक संशोधित भंडारण प्रभार
1.	भंडारण दिवस (0-10 दिन)	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
2.	भंडारण दिवस (11-15 दिन)	2.06	2.11	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
3.	भंडारण दिवस (16-20 दिन)	4.11	4.21	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
4.	भंडारण दिवस 21वें दिन से आगे	8.22	8.43	8.22	8.43

टिप्पणी:

- 20 निशुल्क दिन प्रदान किये जाएंगे। पोत से कार्गो पूरी तरह उतार लिए जाने वाले दिन के अगले दिन से निशुल्क अवधि की गणना के लिए सीमा शुल्क अधिसूचित छुट्टि और टर्मिनल के गैर कामकाजी दिन शामिल नहीं किए जाएंगे।
- भंडारण प्रभार प्रदत्त निःशुल्क अवधि के बाद भी कार्गो के ठहरने के लिए टर्मिनल के गैर कामकाजी दिनों और सीमा शुल्क अधिसूचित छुट्टियों समेत सभी दिनों के लिए देय होगा।
- कार्गो पर भंडारण प्रभार उस अवधि के लिए नहीं जुड़ेगा जिसमें टर्मिनल प्रचालक, उन कार्गो से उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर कार्गो सुपुर्दगी देने की। पोत लदान करने की स्थिति में न हो जिनके लिए टर्मिनल प्रचालक जिम्मेदार ठहराया जा सके।
- उक्त भंडारण अनुसूची 20 जनवरी 2020 तक मान्य होगी और यह स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं बीपीटी द्वारा समीक्षा नहीं किए जाने और इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाने पर दिनांक 11 जनवरी 2013 के आदेश में उचित सूचीबद्ध दरों के साथ यथा अनुमोदित मूल भंडारण सूची दिनांक 21 जनवरी 2020 से लागू होगी।

15.2. बीजीसीबीपीएल को यह भी निदेश दिया जाता है कि वह प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के भीतर बीपीटी के माध्यम से प्रहस्तित कार्गो-वार मात्रा सहित वास्तविक निष्पादन रिपोर्ट और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 2 महीने के भीतर, वास्तविक और वित्तीय दोनों ही, का वार्षिक निष्पादन इस प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/अस./183/19]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 6th August, 2019

No. TAMP/9/2019-VPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in pursuance of Ministry of Shipping letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 on Stressed PPP Projects, the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for amendment in the Storage schedule approved by this Authority vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying Scale of Rates (SOR) in the name of Vizag General Cargo

Berth Pvt. Ltd. (VVCBPL) for mechanized handling of coking coal and steam coal at General Cargo Berth of VPT on DBFOT basis as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/9/2019-VPT

Visakhapatnam Port Trust

Applicant

QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 24th day of July 2019)

This case relates to a proposal dated 7 December 2018 received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for amendment in the Storage Charges approved by this Authority vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying Scale of Rates (SOR) in the name of Vizag General Cargo Berth Pvt. Ltd. (VVCBPL) for mechanized handling of coking coal and steam coal at General Cargo Berth of VPT on DBFOT basis.

2. The main points made by the VPT in its proposal are as follows:

- (i) Upfront tariff for the project has been fixed by TAMP vide its Order dated 27 November 2009 for berth hire, cargo handling charges, storage charges and miscellaneous charges.
- (ii) This project was awarded by VPT to VVCBPL at VPT. The project is completed and operational with effect from April 2013.
- (iii) It has been represented by the VVCBPL that the project is being operated in stressed condition due to various constraints like high storage charges resulting in migration of traffic to the nearby private ports leading to very low capacity utilization.
- (iv) The issue relating to PPP projects in major ports has been raised in various meetings held by the Ministry of Shipping. Considering the importance of the issue, Ministry of Shipping constituted a Committee under the Chairmanship of Chairman IPA to take a decision. The report submitted by the Committee was forwarded by Ministry of Shipping vide file No.PD-13/1/2018-PPP Cell, dated 11-07-2018 to major ports and TAMP directing to adopt the procedure contained therein including review of the situation periodically for optimum utilization of the facility created.

3. The directions of the Ministry were communicated by the VPT to the VVCBPL for remarks. In response, the VVCBPL vide their letters dated 17.10.2018, 02.11.2018 and 12.11.2018 (Annexure-1, 2 & 3) has furnished the relevant data as per the criteria for classification of "Stressed Project" as per the report of the committee. The VVCBPL has also requested to declare VVCBPL as Stressed Asset and to rationalise the storage charges by extending the existing free period by an additional 35 days making the total free period as 45 days.

4. The submissions made by VVCBPL in its letter dated 17 October 2018, 2 November 2018 and 12 November 2018 addressed to VPT are as follows:

A. The VVCBPL in its letter dated 17 October 2018 addressed to VPT and forwarded by VPT along with its proposal has made the following main points:

- (i) In respect of projects that are identified as "Stressed Projects" due to abnormal storage charges, it was suggested that the rationalization of storage charges levied at PPP terminals should be achieved as per Tariff Guidelines, 2008 to make them competitive with neighboring Non-Major Ports which are run by private organization.
- (ii) The Norms for apportionment of total revenue requirement as per upfront tariff guidelines for coal terminal are as follows:

Tariff Group	Percentage of Total revenue allocated
Coal Handling Charges	98
Storage Charges	1
Miscellaneous charges	1

Before explaining the proposed model for idle storage charges, it is worth discussing the current market scenario.

(iii) **Current market scenario**

- (a) The Coal import in the region has increased sharply due to non-availability of domestic coal for Captive power plants, Sponge iron producers, cement manufactures etc. The present market is significantly supporting imports on CAPE vessels to capitalize the freight advantage.
- (b) The availability of rakes is a key factor for evacuation of cargo and thereby the free storage period is key commercial for assessing the commercial feasibility of handling from the terminal. Gangavaram port operates with free storage period of 90-120 days with flexibility for the traders for stock and sale and for end users as just in delivery for easing their working capital. In this competitive environment, VGCBPL is forced to offer a free storage period from 30 to 60 days (average 45 days)
- (c) Despite the market for acute demand of coal, the customers are preferring for more storage period to mitigate the risk of non-availability of rakes. However, in view of optimum usage of our terminal facility VGCBPL have derived the feasible storage period required for various capacity of vessels.

(iv) (a) **Data/inputs from the current markets:**

Particulars	Values	UOM
Average number of rakes available per day	3.50	Rakes
Average capacity of cargo loaded per rake	3,850	MT
Average Cargo dispatch per day through rakes	13,475	MT
Average Cargo dispatch per month through rakes	404250	MT
Days of operation	30	Days
Exchange Rate (₹/US\$)	72	₹/\$

(b) **Vessels handling combination – Assumption**

Vessels	No. of vessels	Qty	Total Qty	Average Discharge	Days for operation per Vessel	GRT per vessels
Cape	1	165,000	165,000	25,000	7	90,000
Panama	3	75,000	225,000	25,000	3	40,000
Total	4		390,000		16	

From the above data, it is clear that a maximum of 400,000 MT can be handled in VGCBPL yard with an average free storage period of 30 days. It is imperative that only VGCBPL is bearing the cost of additional 20 free storage period currently. Beyond this free storage period also, there is a gap between the daily storage charges fixed by TAMP and the actual storage rates collected by VGCBPL. VGCBPL had been providing additional free storage period in order to serve/ retain the customers of the port.

- (v) In line with the Ministry of Shipping guidelines, VGCBPL have worked out a business model which will benefit both M/s.VGCBPL and VPT as well which is summarized below:

Proposed Business Model

- (a) The port authorities were given an opportunity to extend the free period depending on the local conditions with a view to optimize the capacity utilization of the berth with clause for periodical review.

VGCBPL proposes to extend the free period by 35 days (extended free days) beyond the existing 10 free storage days (i.e. 45 days of total free storage period)

- (b) For the cargo staying beyond the extended free days (i.e. 45 days), a maximum tariff of ₹1/- per MT per day would be charged. The other major assumptions of the model are:

Particulars	Values	UOM
Average number of rakes available per day (Assumptions)	4.50	Rakes
Average quantity of cargo loaded per rake	3,850	MT
Average Cargo dispatch per day through rakes	17,325	MT
Average Cargo dispatch per month through rakes	519750	MT
Days of operation	30	Days
Exchange Rate (₹/US\$)	72	₹/\$

(vi) **Final conclusion & proposal**

The following are the proposal proposed by VGCBPL based on the above business model:

- (a) To extend the free period by 35 days (extended free days) beyond the existing 10 free storage days (i.e. total free storage period of 45 days)
- (b) A tariff which is less than or equal to ₹1/- PMT per day would be charged on the cargo stored beyond the free storage period of 45 days (Benchmarking as against the current tariff of ₹0.10 PMT per day in VPT plots and zero for 90 to 120 days in Gangavaram port)
- [The rate prescribed in the existing SOR of VPT for stacking in core operational area is ₹6.21/ sq. mtr./ week for stacking cargo. ₹0.10 PMT per day in VPT plots is not prescribed in the SOR of VPT.]
- (c) The underlying assumption of fixing the dwell time may change dynamically depending upon the market conditions and availability of logistics and can be reviewed periodically (every 6 months or so) for optimum utilization of the facilities.
- (d) The VGCBPL has requested port for remedial actions of notifying the proposal by the Visakhapatnam Port Trust in consultation with the Tariff Authority of Major Ports, Ministry of Shipping on immediate basis so as to provide immediate relief to the terminal operators.

B. Letter dated 2 November 2018 by VGCBPL addressed to VPT gives the rationale behind the proposed free period of 45 days:

- (i) Cape Vessels: For a Cape Vessels, average quantity is 1,65,000 MT. In today's rake availability scenario, not more than one rake per day is allotted for this category of vessel/ customer cargo evacuation. For evacuating the entire cape vessels cargo, VGCBPL would need a total of 42 rakes (@ 3900 MT per rake) and would accordingly need 42 days.
- (ii) Panamax vessels: For a Panamax vessels, average discharge quantity is 75,000 MT. In today's rake availability scenario, not more than one rake per every two days is allotted for this vessel/ customers cargo evacuation. For evacuating the entire panamax vessels cargo, VGCBPL would need a total of 19 rakes (@ 3900 MT per rake) and would accordingly need 38 days.
- (iii) With the above analysis, it is clear that VGCBPL would need a total of 40 to 45 day for evacuating the total cargo (either Cape vessels or panamax vessels) with the current rake availability. It is worth mentioning that the average evacuation time may further increase in case the rakes are not available beyond the above assumptions.

C. The VGCBPL vide its letter dated 12 November 2018 has forwarded Financial Statement of VGCBPL for the years 2016-17 and 2017-18 certified by Chartered Accountant (CA) as regards cash losses/ net worth as given below:

- (i) The cash losses incurred by the VGCBPL in the past have eroded the net worth from ₹151.53 crores in the FY 2012-13 to ₹21.70 crores in the FY 2017-18.

- (ii) The cash losses and net worth of the VGCBPL duly certified by the Chartered Accountant are as under:

Sl. No.	Particulars	FY 2016-17 (₹ in crores)	FY 2017-18 (₹ in crores)
1	Cash Losses incurred by the company	(7.16)	(26.97)
2	Net worth of the company	76.00	21.70

5.1. The VPT has placed the request of VGCBPL in the Board of Trustees meeting of VPT held on 16 November 2018 and the Board has resolved the following:

- (i) Consider the proposal of M/s.VGCBPL for classification of the said project as “Stressed Project” and to treat the project as stressed project in compliance with the direction of Ministry’s order dated 11 July 2018.
- (ii) Approach TAMP under the provision available at Article 21.9 of the Concession Agreement covering “Amendments, Modifications or Alternations” with an appropriate proposal for rationalization of storage charges in consultation with the Concessionaire M/s.VGCBPL so as to achieve the ARR as per the TAMP guidelines/ notifications.
- (iii) Fix the free time for storage of cargo from the existing 10 days as stipulated in the Concession Agreement to 20 days as the same is mutually agreed by both Concessionaire and the Concessioneing Authority for rationalization of storages charges in the TAMP proposal and to inform the Concessionaire to submit a detailed proposal to TAMP through VPT duly justifying the reasonableness of increasing the storage period for rationalization of storage charges.
- (iv) Carry out necessary modifications as per the provisions available under Article 21.9 of the Concession Agreement covering “Amendments, Modifications or Alternations” as per the order of the Ministry dated 11.07.2018.
- (v) Consider the proposal for a period of one year and to review thereafter.

5.2. The VPT has communicated the decision of VPT Board to VGCBPL. The VGCBPL has furnished revised proposal dated 13 December 2018 addressed to VPT, which is summarised below:

- (i) VGCBPL proposes for modification of the notification of Scale of Rates approved by this Authority vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 27 November 2009 notified on 18 December 2009 vide Gazette No.250 pertaining to mechanized handling of coking and steam coal at the General Cargo Berth on DBFOT basis at Visakhapatnam Port in pursuance of the guidelines for upfront tariff setting for Public Private Participation (PPP) projects at Major Ports notified by this Authority vide Notification No.TAMP/52/2007-Misc. dated 26 February 2008.
- (ii) The current SOR has a free storage period of 10 days which is as envisaged at the time of bidding based on the conditions prevailing at the time of conceiving the project, whereas in actual practice it has been observed that the average dwell time is around 20 to 25 days. The storage charges worked out as a % of overall handling charges are much higher than the envisaged 1% in the policy guidelines on Annual Revenue Requirement (ARR) notified by TAMP vide notification dated 26 February 2008.
- (iii) VGCBPL has not been able to achieve the proposed ARR through realization of tariff. The tariff cap for different individual services is, therefore, to be set appropriately by TAMP in such a way as to achieve the ARR as per clause 3.8.2. of the upfront tariff guidelines.
- (iv) For the identified stressed assets, it was informed by the MOS vide its letter dated 11 June 2018 that necessary authority has been granted to the VPT for extending the free period depending on the local conditions with a view to optimize the capacity utilization of the berth with periodical review.
- (v) As per the present condition, VGCBPL is to be declared as Stressed Project and same has been confirmed by VPT in its letter dated 12 December 2018.
- (vi) After, having multiple rounds of discussions, it has been decided to increase the free storage period from existing 10 days (as per the Concession Agreement) to 20 days which is agreed by the VPT also. The justification for the increase proposed in free period is given below:
 - (a) As per the signed Concession Agreement, the free storage period offered is 10 days. This was part of upfront tariff fixed by TAMP vide its Order dated 27 November 2009. The same was decided at the time of bidding based on the market dynamics prevailing that time. Whereas, in actual practice it has been observed that the current market dynamics are completely different than those which are thought of in 2009.

- (b) Describing the current market situations including the rake availability, VGCBPL submitted a letter to VPT vide letter dated 2 November 2018, asking for a revised free storage period of 45 days. Later, in the meeting held with Deputy Chairman and other senior officials of VPT, it has been advised to check the current dwell time of the vessels. In line with the inputs received from VPT, VGCBPL had worked out the dwell time of vessels handled in the past 6 months (data submitted to VPT vide its letter dated 15 November 2018) and noticed that the average dwell time is ranging from 20 to 25 days. Based on the past trend of dwell time, it has been mutually agreed by both the Concessionaire & Concessioning authority to extend the free period upto 20 days.
- (vii) The VPT has informed VGCBPL confirming that the free storage period (which is currently 10 days) has been extended to 20 days (i.e. 10 extended free period) by VPT in pursuance of this authority given by MOS guidelines vide their letter dated 11 July 2018. Accordingly, as per the MOS guidelines VGCBPL will ensure the following:
- (a) No Storage Charges and hence no Royalty if cargo is cleared within the free period as per executed concession agreement (i.e. 10 days)
- (b) If the cargo is cleared after the expiry of free period as per executed concession agreement but within the extended free period, no storage charges will be there but the concessionaire shall pay royalty equal to 1% of ARR and
- (c) If the cargo is cleared after extended free period (i.e. beyond 20 days), concessionaire shall pay Royalty equal to quoted percentage on actual storage charges recovered or 1% of ARR whichever is higher for the period beyond the extended period.
- (viii) Accordingly, the current vs proposed Scale of Rates would be as follows:

Sl. No.	Particulars	Units	Current Scale of Rates	Proposed Scale of Rates
1.	Berth Hire Charges	₹ / GRTH	0.851	0.851
2.	Cargo Handling Charges	₹ / MT	171.69	171.69
3.	Storage Charges (0-10 days)	₹ / MT per day	No Charges	No Charges
4.	Storage Charges (11-15 days)	₹ / MT per day	2.06	No Charges
5.	Storage Charges (16-20 days)	₹ / MT per day	4.11	No Charges
6.	Storage Charges 21 st Day onwards	₹ / MT per day	8.22	8.22
7.	Misc. charges (charges for sweeping, dust suppression and environment, etc.)	₹ / MT	1.76	1.76

[The amendment is proposed in storage charges only.]

- (ix) Further, the current vs proposed royalty on Storage charges would be as under:

Sl. No.	Particulars	Units	* Current Royalty	* Proposed Royalty
1.	Storage Charges (0-10 days)	₹ / MT per day	No royalty	No royalty
2.	Storage Charges (11-15 days)	₹ / MT per day	38.1% of Gross revenue	1% of ARR
3.	Storage Charges (16-20 days)	₹ / MT per day	38.1% of Gross revenue	1% of ARR
4.	Storage Charges 21 st Day onwards	₹ / MT per day	38.1% of Gross revenue	Royalty equal to 38.1% on actual storage charges recovered or 1% of ARR whichever is higher.

[* The mandate of this Authority is to fix SOR. TAMP does not have mandate on Royalty matter which is between port and concerned BOT operators].

- (x) Accordingly, VGCBPL has requested VPT to obtain such orders in consultation with the TAMP which is not inconsistent with the basic features of 2008 Guidelines as may be necessary for removing the difficulty, as per para 1.4 of the upfront tariff guidelines of 2008.

5.3. The VPT has requested this Authority to consider the proposal submitted by VGCBPL and notify the same at the earliest to avoid diversion of cargo to the neighbouring private port and to attract additional volumes so that the capacity utilisation of the facility can be approved. The VPT has further stated that it shall review the proposed rationalisation after one year of notification by this Authority in compliance of VPT Board Resolution and shall approach this Authority for continuation of the proposal or further revision, as the case may be.

6. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of VPT dated 7 December 2018 along with enclosures was forwarded to the concerned users/ user organisations seeking their comments. We have received comments only from Steel Authority of India Limited (SAIL) which was forwarded to VPT for feedback information. The VPT has not furnished its reply till this case was finalised.

7. A joint hearing on this case in reference was held on 17 June 2019 at VPT premises. At the joint hearing, the VPT and VGCBPL have made their submissions.

8. The relevant extract of storage charges schedule and relevant note(i) prescribed in the upfront tariff Order 27 November, 2009 and in the tariff Order dated 11 January 2013 notifying indexed SOR in the name of VGCBPL is given below:

(i) Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 27 November 2009:

“4. STORAGE CHARGES:

The Storage charges for the cargo stored in the stack yard beyond the free period shall be as below:

(Rate in Rs. per tonne per day or part thereof)

Sl. No.	Commodity	Rate for first 5 days for the balance cargo remaining after the free period	Rate for 6 th day to 10 th day for the balance cargo	Rate for 11 th onwards for the balance cargo
1.	Coking coal and Steam coal	1.58	3.16	6.32

Note:

10 free days shall be allowed. Free period shall commence from the day following the day of complete discharge of vessel cargo. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.”

(ii) Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013:

“4. STORAGE CHARGES:

The Storage charges for the cargo stored in the stack yard beyond the free period shall be as below:

(Rate in ₹ per tonne per day or part thereof)

Sl. No.	Commodity	Rate for first 5 days for the balance cargo remaining after the free period	Rate for 6 th day to 10 th day for the balance cargo	Rate for 11 th onwards for the balance cargo
1.	Coking coal and Steam coal	1.80	3.59	7.19

Note:

10 free days shall be allowed. Free period shall commence from the day following the day of complete discharge of vessel cargo. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.”

9.1. The MOS vide e-mail dated 11 July 2018 has issued the letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 regarding Stressed PPP project along with copy of report of the Committee chaired by Chairman, IPA on the issues pertaining to Stressed PPP projects. The said Committee has recommended the following criteria for classification of PPP project as **“Stressed Projects”**:

- (a) The project is sub optimally utilised as evidenced by the actual cargo handled by the operator during two preceding financial years being less than 70% of the projection as per DPR/Feasibility report forming part of the bid document and
- (b) Project SPV incurring cash loss continuously for two preceding financial years and
- (c) That the losses incurred by concessionaire has caused atleast 50% erosion of its peak Net Worth during the operation period.

9.2. Para 6 of the MOS letter dated 11 July 2018 states that whenever issue of abnormal storage charges emerges in stressed projects as defined in the MOS letter, the Ports may approach TAMP under the provisions of "Agreements, modification or alternations" to the terms and conditions of the concession agreement with an appropriate proposal for rationalization of storage charges in consultation with concessionaire so as to achieve the ARR as per the TAMP guidelines/ notification. This Authority has to consider such proposal on merit. The Committee also recommended review of the situation by the Concessioneing Authority periodically for optimum utilization of the facility created.

9.3. Referring to the said letter of MOS, the VPT has filed the current proposal for modification of storage schedule approved by this Authority in the Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying indexed tariff in the name of the VGCBPL based on the upfront tariff approved by this Authority vide Order dated 27 November 2009 for the mechanized handling of coking coal and steam coal at the general cargo berth on DBFOT basis at VPT.

10.1. The proposal of the VPT for increase in free period and amendment in the storage schedule based on approval of its Board of Trustees would have matured for notification only after following the consultation process prescribed, which would have taken time. Hence, keeping in view the approval accorded by the Board of Trustees of VPT for the increase in free period for storage of cargo, and keeping in view the urgency expressed by the VPT, in-principle approval was accorded to the proposal of VPT for amendment in the existing storage schedule of VGCBPL as given below pending approval of this Authority and its notification in the Gazette of India after following the consultation process prescribed and was conveyed to the VPT vide our letter dated 21 January 2019:

Storage Charges:

(in ₹ per tonne per day or part thereof)

Sl. No.	Storage Days	Existing Rate of VGCBPL as per Current SOR	Amended Storage Charges
1.	0-10 days	NIL	NIL
2.	11-15 days	2.06	No Charge
3.	16-20 days	4.11	No Charge
4.	21 st day onwards	8.22	8.22

10.2. As regards the proposal of the VPT which also included the revenue share payable by the VGCBPL, it was brought to the notice of the VPT that the percentage of Revenue share on the storage charges payable by the VGCBPL to VPT will be governed as per MOS letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 issued on Stressed PPP Projects.

11. Subsequently, the VPT vide its e-mail dated 5 July 2019 has clarified the following as regards the first criteria prescribed in the MOS letter dated 11 July 2018:

- (i) Criteria 3(a) for classification of a PPP project as 'Stressed Project' stipulates that "the project is sub-optimally utilized as evidenced by the actual cargo handled by the operator during two preceding Financial years being less than 70% of the projection as per DPR/Feasibility report forming part of the bid document."
- (ii) In this regard, VPT Board in its meeting held on 16.11.2018 opined to consider the VGCB as Stressed Project. Statement showing the utilisation of VGCB considered by VPT Board for classification of the project as stressed project with reference to the said criteria is given as under:

Year	Quantity (MMT)	% Utilization
2016-17	4.25	42%
2017-18	5.53	54%

12.1. Further, the submissions of VGCBPL vide its letter dated 10 July 2019 are summarised below:

- (i) TAMP has completed the public consultation for amendment in the Storage Schedule approved by the Authority vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11.01.2013 notifying the Scale of Rates (SOR) in the name of VGCBPL. The public consultation was conducted at VPT offices on 17.06.2019.
- (ii) This project by VGCBPL had commenced its commercial operations from 08.04.2013 and was envisaged with a daily unloading capacity of 42000 to 70000 metric tons depending on the size of

vessel, with a free storage period of 10 days, and with an anticipated availability of ten railway rakes per day.

- (iii) As per the TAMP guidelines on Annual Revenue Requirement (ARR) of 2008, the coal handling terminal has to earn 98% revenue through handling charges, 1% revenue through Storage Charges and 1% towards miscellaneous charges. However, since the commencement of operations from 08.04.2013, all stakeholders including Ministry of Shipping, VPT and TAMP have noted that the revenue from storage charges at the VGCBPL terminal in VPT is around 25 to 45 percent (instead of 1%) which is abnormal and driving away the customers from this terminal to the neighbouring minor ports.
- (iv) In July 2018 when the Ministry of Shipping vide their letter No.PD-13/1/2018-PPP cell dated 11.07.2018 has recommended the Major Ports to adopt procedures for rationalisation of storage charges in consultation with the Concessionaires so as to achieve the ARR as per the TAMP guidelines/ notification and TAMP was asked to consider the proposal on merit.
- (v) While amending, VGCBPL has requested to do the needful by asking both the Concessioning Authority and the Concessionaires to have a mutually agreeable effective date for computing the impact of the change in scale of rates.

12.2. The new point made by the VGCBPL in the said communication is point no.(v)

13. The proceedings relating to joint hearing held in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made by the parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

14. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

- (i) The proposal mooted by the Visakhapatnam Port Trust (VPT) seeks approval of this Authority for increase in existing free period and amendment in the existing Storage schedule in the SOR of the BOT operator, Vizag General Cargo Berth Pvt. Ltd. (VGCBPL) operating in the VPT who is governed by the upfront tariff guidelines of 2008, in pursuance of Ministry of Shipping (MOS) letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 issued to all Major Ports to deal with Stressed PPP projects.
- (ii) As already brought out in the earlier paragraphs, this Authority had vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 27 November 2009 passed an Order relating to fixation of upfront tariff for the mechanised handling of coking coal and steam coal at its General Cargo Berth (GCB) on Design Built Finance Operate and Transfer (DBFOT) basis at VPT under the upfront tariff guidelines of 2008 in compliance with the upfront tariff guidelines of 2008 issued by the MOS and effective from 26 February 2008.

The VPT has awarded the project to M/s.VGCBPL. In compliance of the said provisions of Guidelines, the SOR was notified in the name of VGCBPL vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 after indexing the notified upfront tariff approved by this Authority in the tariff Order of 27 November 2009.

- (iii) The current proposal of VPT is taken up for processing because it is filed in pursuance of the MOS letter dated 11 July 2018 to the Major Port Trusts as regards the stressed PPP project.
- (iv) The MOS in its letter dated 11 July 2018 has prescribed the three criteria for classification of PPP project as Stressed Projects by Major Port Trusts which has been brought out in para 9.1. above and hence not reiterated for the sake of brevity. The Board of Trustees of the VPT has declared the project handled by the VGCBPL as Stressed Project. The port has furnished the following as regards the three criteria prescribed in the MOS letter which has been considered by the Board of Trustees of the VPT for declaring the project of VGCBPL as Stressed Project:

- (a) As regards the first parameter, the capacity utilisation for the preceding two years furnished by the VPT being below 70% as exhibited by VPT is tabulated below:

Year	Quantity (MMT) of cargo handled	% Utilization
2016-17	4.25	42%
2017-18	5.53	54%

- (b) As regards the other two parameters, the port has furnished the certificate issued by the Chartered Accountant reporting cash loss continuously for two preceding financial years and erosion of net worth beyond 50% in the preceding two years:

Sl. No.	Particulars	FY 2016-17 (₹ in crores)	FY 2017-18 (₹ in crores)
1	Cash Losses incurred by the company	(7.16)	(26.97)
2	Net worth of the company	76.00	21.70

From above it is seen that the cash losses has increased from ₹ 7.16 crores in the financial year 2016-17 to ₹ 26.97 crores in the year 2017-18. Further, the net worth of the VGCBPL has eroded from ₹ 76 crores in financial year 2016-17 to ₹ 21.70 crores in financial year 2017-18 which is 71% i.e. more than at least 50% erosion prescribed as one of the criteria for declaring the project as stressed project.

- (v) The upfront SOR approved by this Authority vide Order dated 27 November 2009 and the SOR approved by this Authority and notified in the name of the VGCBPL prescribes the following provision as regards free period under Schedule 4 Note no.1.

“10 free days shall be allowed. Free period shall commence from the day following the day of complete discharge of vessel cargo. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.”

The proposal of the port is to increase the free period from existing 10 days to 20 days and consequently amend the existing storage schedule. Accordingly, a comparative position of storage schedule as per the upfront tariff approved by this Authority vide its Order dated 27 November 2009, as per SOR notified in the name of the VGCBPL vide Order dated 11 January 2013, existing applicable rate after applicable automatic indexation for the year 2018-19 and current year 2019-20 from April 2019, and the storage charges proposed by VPT and that approved by this Authority after minor correction in the rate are given below:

(₹/MT tonne per day or per day)

Sl. No.	Particulars	Storage Charges approved by this Authority vide Order dated 27 November 2009	Storage Charges in the SOR notified in the name of VGCBPL vide Order dated 11 January 2013 after applicable indexation factor	Storage Charges applicable for the year 2018-19 after applicable indexation	Proposed Storage Charge by VPT vide its letter dated 7 December 2018	Storage Charges proposed by VPT based on existing rate approved after updating it with applicable annual indexation factor for the year 2019-20 applicable from 1 April 2019
1.	Storage Charges (0-10 days)	Nil	Nil	No Charges	No Charges	No Charges
2.	Storage Charges (11-15 days)	1.58	1.80	2.06	No Charges	No Charges
3.	Storage Charges (16-20 days)	3.16	3.59	4.11	No Charges	No Charges
4.	Storage Charges 21 st day onwards	6.32	7.19	8.22	8.22 *	8.22 * (from 21.01.2019 upto 31.03.2019) # # 8.43 # (from 01.04.2019 till 20.01.2020)

(* The storage charge applicable for the year 2018-19 is arrived after applying applicable compounded indexation of 27.49% over the base year 2009 till 2017-18 and annual indexation of 2.07% for the year 2018-19.

The storage charge applicable for the year 2019-20 is arrived after applying applicable annual indexation of 2.56% announced by this Authority vide letter No.TAMP/12/2009-Misc. dated 29 March 2019 for the year 2019-20.)

21.01.2019 is the date of communication of in-principle approval.

- (vi) Recognizing that the proposal filed by the VPT is based on the approval of the Board of Trustees of the VPT and is based on the MOS letter dated 11 July 2018 on the Stressed Project and is for a period of one year and to be reviewed thereafter by the Board of Trustees of the VPT, and is mutually accepted by both the parties i.e. VPT and VGCBPL and is intended to improve the utilization of the facility created, this Authority is inclined to approve the current proposal of the port. The VPT had filed the proposal in December 2018. Since the automatic annual indexation in the upfront tariff notified by this Authority is applicable for the year 2019-20 from 1 April 2019 as per letter No.TAMP/12/2009-Misc. dated 29 March 2019, the updated storage charge after applying the applicable annual indexation factor

of 2.56% from 1 April 2019 as announced by this Authority needs to be incorporated i.e. ₹8.43/ tonne/ day or part thereof instead of ₹8.22/ tonne/ day or part thereof proposed by VPT.

- (vii) As brought out in the preceding paragraph, for the reasons stated, in principle approval was accorded to the proposal of the VPT dated 7 December 2018 vide our letter dated 21 January 2019. As stated earlier, the Board of VPT has accorded approval to the proposal for one year and review thereafter. That being so, validity of the amended storage schedule is approved by this Authority for the period of one year from 21 January 2019 till 20 January 2020. The amended storage schedule would stand lapsed automatically and the original storage schedule as notified vide Order dated 11 January 2013 with applicable indexation would come into effect from 21 January 2020 unless reviewed by VPT and approved by this Authority.
- (viii) As regard the point made by VGCBPL to do the needful by asking both VPT and VGCBPL to have a mutually agreeable effective date of hearing, it is to state that the MOS has issued letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 to all Major Ports on Stressed PPP Projects. The said letter of the MOS requires the Major Port Trusts to file an appropriate proposal for rationalization of storage charges in consultation with concessionaire as regards stressed project based on the criteria for stressed project prescribed by the MOS. The VPT has filed the proposal dated 7 December 2018 in pursuance of the said letter of the MOS and with the approval accorded by its Board on 16 November 2018. For the reasons stated in the earlier paragraphs of this Order, the proposal of the VPT for increase in free period and rationalised storage charge has been recommended for approval from 21 January, 2019 for period of one year till 20 January 2019 and it shall automatically lapse unless reviewed by VPT and approved by this Authority. As regards the point made by the VGCBPL for mutually agreeable effective date between the VGCBPL and VPT, it is for the VPT and the VGCBPL to look into the matter.
- (ix) The proposal of VPT also proposes the royalty payable as brought out in an earlier paragraph. In this regard, it is to state that the mandate of this Authority is to fix Scale of Rates. This Authority does not have the mandate on Royalty matter which is between the port and the concerned BOT operator. Thus, as regards the proposal of the VPT covering percentage of revenue share on the storage charges payable by the VGCBPL to VPT, it is stated that the port will be governed by the MOS letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018. This position was already brought out in our letter dated 21 January 2019.
- (x) Since the current proposal of the VPT is for a limited period of one year and recognizing that the storage charge and the free period prescribed in the SOR notified in the name of the VGCBPL is for the entire project subject to annual escalation, it is found appropriate to prescribe the existing note (i) as regards increase in free period from 10 days to 20 days and amended storage schedule proposed by the VPT separately instead of tinkering with the existing Scale of Rates of the VGCBPL approved by this Authority in the Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013. Note Nos.(ii) and (iii) relating to storage charge as per the Schedule 4 in the SOR notified in the said Order is prescribed herein for ease of application.

15.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority replaces the existing schedule as per the Schedule 4 in Order approved by this Authority vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying the SOR in the name of the VGCBPL with the following schedule:

(in ₹ per tonne per day or part thereof)

Sl. No.	Particulars	Storage Charges applicable for the year 2018-19 after applicable indexation	Existing Storage Charges applicable for the year 2019-20 after applicable indexation	Amended Storage Charges from 21.1.2019 till 31.3.2019	Amended Storage Charges from 1.4.2019 till 20.1.2020
1.	Storage Charges (0-10 days)	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges
2.	Storage Charges (11-15 days)	2.06	2.11	No Charges	No Charges
3.	Storage Charges (16-20 days)	4.11	4.21	No Charges	No Charges
4.	Storage Charges 21 st Day onwards	8.22	8.43	8.22	8.43

Notes:

- (i) 20 free days shall be allowed. Free period shall commence from the day following the day of complete discharge of vessel cargo. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.
- (ii) Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non-working days and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.
- (iii) Storage charges on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver/ ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the Terminal operator.
- (iv) The above storage schedule shall be valid till 20 January 2020 and it shall automatically lapse and the original storage schedule as approved in the Order dated 11 January 2013 with appropriate indexation rates shall come into effect from 21 January 2020, unless reviewed by VPT and approved by this Authority.

15.2. The VGCBPL is also directed to furnish the quarterly physical performance including the cargo-wise volume handled through VPT within 15 days on the end of each quarter and annual performance both physical and financial within 2 months at the end of the financial year to this Authority.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./183/19]